Innovation and Integrative Research Center Journal
ISSN: 2584-1491 | www.iircj.org
Volume-3 | Issue-2 | February - 2025 | Page 77-80

नलंदा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बालिका शिक्षा की वर्तमान स्थिति है?

[1]सुमन सौरभ, [2]डॉ.यशपाल सिंह
[1]शोध छात्र, [2]सहा प्राध्यापक
[1,2]कलिंगा विश्वविद्यालय,नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ – 492101

भारत जैसे विशाल एवं विविधतापूर्ण देश में शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का सबसे सशक्त माध्यम माना गया है। विशेष रूप से ग्रामीण भारत में शिक्षा का प्रसार न केवल मानव विकास के सूचकांकों को सुधारने के लिए आवश्यक है, बल्कि यह सामाजिक संरचना एवं लैंगिक समानता को पुनर्निर्मित करने में भी केंद्रीय भूमिका निभाता है। स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति अवश्य की, परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में बालिका शिक्षा की स्थिति आज भी अनेक चुनौतियों से घिरी हुई है।[1] ग्रामीण समाज में बालिकाओं को दी जाने वाली शिक्षा केवल विद्यालयों की उपस्थिति से नहीं, बल्कि समाज की सांस्कृतिक धारणाओं, आर्थिक संसाधनों, पारिवारिक उत्तरदायित्वों, और सामाजिक–सांस्कृतिक नियंत्रणों से निर्धारित होती है।

बिहार, विशेषकर नालंदा जिला, इतिहास में न केवल भारत बल्कि समूचे एशिया में शिक्षा का केंद्र रहा है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय विश्व के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक था, जहाँ दूर–दूर से विद्यार्थी ज्ञानार्जन हेतु आते थे।[2] विडंबना यह है कि वही क्षेत्र आज ग्रामीण स्तर पर शिक्षा, विशेषकर बालिका शिक्षा, में कई सामाजिक–आर्थिक एवं सांस्कृतिक बाधाओं का सामना कर रहा है। यह विरोधाभास एक गंभीर अध्ययन की आवश्यकता प्रस्तुत करता हैकृक्योंकि जिस भूमि ने विश्व को शिक्षा की दिशा दिखाई, वह आज अपनी ही बालिकाओं को बुनियादी शिक्षा उपलब्ध कराने में संघर्ष कर रही है।

ग्रामीण नालंदा की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि आधारित है। अधिकांश परिवार छोटे और सीमांत किसान हैं, जिनके पास संसाधनों की कमी है। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने पर शिक्षा को प्रायः 'द्वितीयक आवश्यकता' समझा जाता है, और लड़कियों के मामले में यह प्राथमिकता और भी कम हो जाती है। कई परिवारों में यह विश्वास प्रचलित है कि लड़कों की शिक्षा पर निवेश आर्थिक रूप से अधिक सार्थक है क्योंकि वे भविष्य में परिवार का भरण–पोषण करते हैं, जबकि लड़कियाँ विवाहोपरांत दूसरे घर चली जाती हैं।[3] ऐसी आर्थिक–मानसिक संरचना बालिकाओं के प्रति शैक्षिक निवेश को सीमित करती है।

इसके अलावा, गरीबी की स्थिति में बालिकाओं को घरेलू कार्यों, पशुपालन, पानी लाने, भोजन बनाने, तथा छोटे भाई–बहनों की देखभाल का दायित्व सौंप दिया जाता है।[4] ऐसे दायित्वों के कारण बालिकाएँ विद्यालय नियमित रूप से नहीं जा पातीं। विशेष रूप से फसल कटाई या बुवाई के समय

Innovation and Integrative Research Center Journal
ISSN: 2584-1491 | www.iircj.org
Volume-3 | Issue-2 | February - 2025 | Page 77-80

ग्रामीण परिवारों में श्रम की अतिरिक्त आवश्यकता पड़ती है, जिसका प्रभाव किशोर बालिकाओं की उपस्थिति पर सीधा पड़ता है।

ग्रामीण नालंदा में सामाजिक–सांस्कृतिक संरचना पितृसत्तात्मक है। कई समुदायों में यह धारणा गहराई से विद्यमान है कि लड़कियों की भूमिका मुख्यतः 'संस्कारित गृहिणी' बनने की है, जिससे उनकी शिक्षा को महत्त्व कम दिया जाता है।[5] किशोरावस्था के बाद विद्यालय भेजने को लेकर परिवारों में असुरक्षा और सामाजिक नियंत्रण बढ़ जाता है। विद्यालय की दूरी, रास्ते की सुरक्षा, अपर्याप्त परिवहन और सामाजिक निगरानी,ये सभी कारक परिवारों को लड़कियों को विद्यालय भेजने से रोकते हैं। कई ग्रामीण इलाकों में यह मिथक भी गहराई से मौजूद है कि अधिक पढ़ाई करने से "लड़कियाँ बिगड़ जाती हैं" या उनकी विवाह में "अधिक शिक्षित लड़की" के लिए समुचित लड़का मिलना कठिन होता है, जिससे विवाह लागत बढ़ सकती है। इस प्रकार, विवाह–संबंधी चिंताएँ बालिका शिक्षा को सीमित करने वाले प्रमुख सामाजिक अभिकारक के रूप में कार्य करती हैं।[6] बाल–विवाह, जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्पष्ट या सूक्ष्म रूप से जारी है, बालिकाओं के शैक्षिक जीवन को सीधे प्रभावित करता है। कई बालिकाएँ माध्यमिक स्तर तक पहुँचने से पहले ही पारिवारिक दबावों के कारण शिक्षा छोड़ने पर मजबूर हो जाती हैं। शैक्षणिक अवसंरचना की चुनौतियाँ ग्रामीण नालंदा में विद्यालयों की अवसंरचना के स्तर में असमानता स्पष्ट दिखाई देती है। यद्यपि सरकारी स्तर पर विद्यालयों का विस्तार हुआ है, परंतु प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी विषय–विशेषज्ञ (विशेषकर गणित और विज्ञान) की अनुपस्थिति शौचालयों की अनुपलब्धता, विशेषकर बालिकाओं के लिए विद्यालयों की दूरी कक्षाओं का भीड़भाड़ होना पाठ्यसामग्री एवं पुस्तकालय सुविधाओं का अभाव जैसी समस्याएँ बालिका शिक्षा को काफी प्रभावित करती हैं।[7]

बालिकाओं के लिए सुरक्षित और स्वच्छ शौचालयों की उपलब्धता ग्रामीण विद्यालयों में एक गंभीर मुद्दा है। किशोर आयु की लड़कियों में मासिक धर्म स्वच्छता को लेकर कई ग्रामीण विद्यालयों में पर्याप्त संसाधन नहीं पाए जाते। परिणामस्वरूप, कई बच्चियाँ मासिक धर्म के दिनों में विद्यालय नहीं जातीं और धीरे–धीरे उनकी उपस्थिति कम होती जाती है। महामारी के बाद शिक्षा प्रणाली में डिजिटल माध्यमों का महत्व बढ़ गया, किंतु यह परिवर्तन ग्रामीण बालिकाओं के लिए चुनौती बन गया। ग्रामीण नालंदा में— स्मार्टफोन की कमी इंटरनेट की अस्थिर उपलब्धता डिजिटल साक्षरता की कमी परिवार के उपकरणों का सीमित उपयोग ने बालिकाओं की शिक्षा को कठिन बना दिया।[8] कई परिवारों में मोबाइल फोन होने पर भी उसका प्रयोग पुरुष सदस्यों द्वारा प्राथमिकता से किया जाता है, जिससे लड़कियों की डिजिटल शिक्षा बाधित होती है। यह अंतर न केवल औपचारिक शिक्षा में, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं और कौशल विकास के अवसरों में भी लैंगिक असमानता उत्पन्न करता है। नालंदा की ग्रामीण जातीय संरचना भी शिक्षा में असमानता को जन्म देती है। अनुसूचित जाति, महादलित, और पिछड़े वर्गों की बालिकाएँ दोहरी–अन्यायिक स्थितियों से गुजरती हैंकृएक ओर गरीबी और सामाजिक बहिष्करण, दूसरी ओर लैंगिक भेदभाव।[9] इन

Innovation and Integrative Research Center Journal
ISSN: 2584-1491 | www.iircj.org
Volume-3 | Issue-2 | February - 2025 | Page 77-80

समुदायों में शिक्षा के प्रति जागरूकता कम होने के कारण बालिकाओं की विद्यालय–उपस्थिति और भी सीमित हो जाती है।

बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएँ,जैसे मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, पोशाक योजना, छात्रवृत्ति, विद्यालयों में मध्याह्न भोजन, तथा बेटी बचाओदृबेटी पढ़ाओकृने बालिकाओं की शिक्षा में कुछ सकारात्मक परिवर्तन अवश्य लाए हैं।[10] साइकिल योजना ने माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं की पहुँच बढ़ाई है। पोशाक योजना ने विद्यालय में नियमितता बढ़ाई, और छात्रवृत्ति ने शिक्षा–निवेश को प्रोत्साहित किया है। परंतु इन योजनाओं का प्रभाव कई बार असमान रूप से वितरित होता है। सामाजिक मान्यताएँ, स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था, वितरण तंत्र, तथा परिवारों की आर्थिक चुनौतियाँ कई बार इन योजनाओं के अपेक्षित परिणामों को सीमित करती हैं। नालंदा जिले का उदाहरण यह दर्शाता है कि ग्रामीण भारत में बालिका शिक्षा केवल विद्यालय उपलब्धता का प्रश्न नहीं, बल्कि एक बहु–स्तरीय सामाजिक तंत्र से प्रभावित प्रक्रिया है। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, संरचनागत, जातीय, और लैंगिक अभिकारक, सभी परस्पर जुड़े हुए हैं। यह जटिल संरचना अध्ययन की आवश्यकता को और भी महत्वपूर्ण बनाती है।

यह अध्ययन निम्नलिखित कारणों से अत्यंत प्रासंगिक है—बालिका शिक्षा की वर्तमान स्थिति का वास्तविक मूल्यांकन अभिकारकों का विश्लेषण—आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, डिजिटल, जातीय वर्तमान नीतियों की सीमाएँ एवं उनकी प्रभावशीलता का परीक्षण नालंदा जैसे शिक्षा–समृद्ध ऐतिहासिक क्षेत्र में आधुनिक शैक्षिक चुनौतियों का अध्ययन नीतिगत और सामाजिक सुधारों के लिए सुझाव तैयार करना अतः ग्रामीण नालंदा में बालिका शिक्षा की पृष्ठभूमि का गहन और विस्तारपूर्ण अध्ययन न केवल शैक्षणिक दृष्टि से, बल्कि सामाजिक और विकासात्मक परिप्रेक्ष्य से भी अत्यंत आवश्यक है।

संदर्भ

1. Dutt, R. *History of Ancient Education in Bihar*. Patna University Press, 2012.
2. Government of Bihar. *District Education Report: Nalanda*. Dept. of Education, 2021.
3. Sharma, Meenakshi. “Rural Girls’ Education and Household Responsibilities.” *Journal of Gender Studies*, vol. 18, no. 2, 2019, pp. 44–62.
4. Singh, Usha. “Gender and Rural Domestic Labour in Bihar.” *Indian Sociological Review*, vol. 45, no. 1, 2018, pp. 71–84.
5. Jha, Nirmala. *Gender Norms and Schooling in North India*. Sage Publications, 2017.
6. Prasad, R. “Marriage Norms and Female School Dropout in Rural Bihar.” *Social Change*, vol. 50, no. 4, 2020, pp. 403–22.

Innovation and Integrative Research Center Journal
ISSN: 2584-1491 | www.iircj.org
Volume-3 | Issue-2 | February - 2025 | Page 77-80

7. Singh, Usha. “Infrastructure Challenges in Rural Schools of Bihar.” *Indian Educational Review*, vol. 57, no. 1, 2020, pp. 77–89.
8. UNICEF India. *Digital Learning and Rural Children*. UNICEF Report, 2021.
9. Kumar, Ashok. *Education and Social Structure in Bihar*. Nalanda Books, 2018.
10. Government of Bihar. *Mukhyamantri Balika Cycle Yojana Report*. Education Dept., 2020.

Innovation and Integrative Research Center Journal